54 महीनों के बाद देश की एयर ट्रैवल ग्रोथ रुकी!

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (ए)। भारत का घरेलू एयर ट्रैवल की ग्रोथ 52 महीनों तक दहाई और फिर 2 महीने तक इकाई अंक में बढ़ने के बाद अब फ्लैट रही है। मार्च 2019 में देश में 1,15,96,000 घरेलू यात्रियों ने सफर किया जो कि पिछले साल इसी महीने सफर करने वाले 1,15,80,000 यात्रियों की तुलना में सिर्फ 0.1 प्रतिशत ज्यादा है। ऐसा देश में प्लेन के अचानक बंद हो जाने के चलते हुआ है। 13 मार्च को स्पाइस जेट ने 13 बोइंग 737 मैक्स विमान बंद कर दिए थे। इसी महीने जेट एयरवेज को अपने 35 विमान बंद करने पड़े थे।

हवाई किराए में हुई बढ़ौतरी

सभी घरेलू हवाई यात्रियों में से एक तिहाई हवाई यात्रियों ने कम दाम वाली कैरियर्स से यात्रा की। हालांकि, इस साल मार्च में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में पहली बार 76.9 प्रतिशत घरेल यात्रियों ने बजट एयरलाइंस में सफर किया। बाकी के 23.1 प्रतिशत यात्रियों ने एयर इंडिया, जेट और विस्तारा के साथ सफर किया। फ्लाट्स की घटती क्षमता के चलते हवाई किराए बढ़े और इसके चलते कम लोगों ने हवाई यात्रा का विकल्प चुना। कैंसलेशन की बात करें तो मार्च 2019 के डीजीसीए डेटा से पता चलता है 2.7 लाख घरेलू यात्रियों ने अपनी फ्लाइट्स छोड़ दीं। जिन यात्रियों की फ्लाइट्स सबसे ज्यादा कैंसल हुईं उनमें स्पाइस जेट (2.3 लाख यात्री) और जेट एयरवेज (26,185 यात्री) शामिल हैं। फ्लाइट्स रद्द होने का परिणाम यह हुआ कि कम लोगों ने हवाई सफर का विकल्प चुना। पिछले 5 सालों में भारतीय एविएशन इंडस्ट्री ने ऐसी ग्रोथ का सामना किया। 2018 की शुरुआत में तेल की कीमतें कम हुई थीं और एयरलाइंस ने किराया घटाते हुए हवाई सफर को ज्यादा किफायती बनाया था।

अब जबकि जेट बंद हो चुकी है और इसके दोबारा चालू होने की उम्मीद इसकी बिक्री प्रक्रिया पर निर्भर है। सरकार दूसरी एयरलाइंस से अपने एयरक्राफ्ट की आवाजाही बढ़ाने को कह रही है ताकि जेट एयरवेज के बंद होने से खाली हुए गैप को भरा जा सके। एयरलाइन अधिकारियों ने चेतावनी दी थी, पूरी तरह से चोक रहने वाले दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू एयरपोर्ट पर अचानक स्लॉट उपलब्ध होने से अब हम और प्लेन अपने बेड़े में शामिल करेंगे। तेल के दाम 80 डॉलर प्रति बैरल और एक डॉलर की कीमत 70 रुपए तक आने से चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं हैं। आने वाली सरकार को जेट फ्यूल पर लगने वाले टैक्स पर पुर्नविचार करना चाहिए क्योंकि दुनियाभर की तुलना में देश में घरेलू फ्लाइट्स के लिए ईंधन की कीमतें सबसे ज्यादा महंगी हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में कई और किंगफिशर और जेट एयरवेज देखने को मिल सकती हैं। अक्टूबर 2018 एविएशन इंडस्ट्री के लिए लगातार ऐसा 50वां महीना रहा था जबकि ग्रोथ दोहरे अंकों में देखी गई थी। इन महीनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ करीब 30 प्रतिशत 2015-16 के कुछ महीनों में हुई लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि जेट फ्यूल की महंगाई, रुपए में गिरावट और कम क्षमता जैसे कई कारणों के चलते एयरलाइंस किराया बढ़ा रही हैं। इसके चलते ही ग्रोथ रेट में गिरावट हो रही है लेकिन फिर भी इसने एक संतोषजनकल स्तर कायम रखा था। दिसंबर 2018 आखिरी महीना था जबकि यह ग्रोथ दहाई के अंकों में रही। इस महीने में कुल 1.3 करोड़ घरेलू यात्रियों ने हवाई सफर किया जो पिछले साल 2018 की तुलना में 12.9 प्रतिशत ज्यादा था। जनवरी और फरवरी में, घरेलू ग्रोथ रेट क्रमशः 9.1 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत रही। लेकिन बोइंग 737 मैक्स के बंद होने और जेट संकट ने ग्रोथ को पूरी तरह रोक दिया है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट के लिए पिछला काफी समय ग्रोथ के लिहाज से बेहतर साबित हुआ था।

20 हजार से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करने वालों को मिला टैक्स नोटिस

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (ए)। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में तय नियम से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन करने वालों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने ऐसे करीब 27 हजार लोगों की पहचान की है। इनकम टैक्स जांच में 26,830 मामले सामने आए हैं। करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन हुआ।

सभी मामले वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान के हैं। वहीं 5 लाख से ज्यादा कैश लेनदेन के करीब 10,000 मामले सामने आए हैं। आईटी एक्ट धारा 271 के मुताबिक कैश के बराबर जुर्माना लग सकता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 20,000 से ज्यादा कैश लेनदेन पर पाबंदी है। दिल्ली में करीब 2000 और हैदराबाद के 1700 मामले सामने आए हैं। अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन किया है तो मुश्किल में फंस सकते हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। इनकम टैक्स विभाग के सेक्शन 269SS, 269T के तहत अगर कोई 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उसे उतने ही अमाउंट का जुर्माना लगेगा।

कैश लेन-देन पर नियम सख्त: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स के नियमों को लेकर आम आदमी को समय-समय पर जागरूक करता रहता है। इसी के तहत विभाग ने साफ किया है कि आप घर खरीदने व बेचने के दौरान 20,000 से ज्यादा का कैश में लेन-देन नहीं कर सकते। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक एडवायजरी भी जारी की है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। दोषी पाए जाने पर आयकर विभाग आप पर इसके लिए पेनल्टी वसूल सकता है।

क्या है नियम: 20 हजार रुपए से ज्यादा का कैश लेने पर आयकर विभाग ने कई तरह के नियम बनाए हुए हैं।

200 से अधिक कंपनियों में 1 लाख करोड़ रु. का घपला

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (ए)। दिसंबर 2016 में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वंसी रेजॉलुशन का प्रावधान लागू होने के बाद 200 से अधिक कंपनियों की फॉरेंसिक ऑडिट से एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के घपले की जानकारी मिली है। भारतीय उद्योग जगत में घपले-घोटालों की बाढ़ से आई हुई है। इसका खुलासा दिवालिया कानून के तहत हो रही जांच में हुआ है। खबर है कि इन्सॉल्वंसी ऐंड बैंकरप्ट्सी कोड (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वंसी रेजॉलुशन का सामना कर रहीं इन कंपनियों से फंड डायवर्जन की भी आशंका है।

कड़ी कार्रवाई की उम्मीद

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जिन दर्जनभर हाई प्रोफाइल मामलों को आईबीसी के तहत रेजॉलुशन के लिए नामित किया, उनमें ज्यादातर में गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसलिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जैसी एजेंसियां भी इनकी अलग से जांच कर रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अब कंपनी मामलों का मंत्रालय इन कंपनियों के प्रमोटरों, डायरेक्टरों और कुछ कंपनियों के ऑडिटरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा। कुछ सूत्रों ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि कॉर्पोर्ट मिनिस्ट्री पर ही आईबीसी को लागू करने की जिम्मेदारी है।

इन कंपनियों में धोखाधड़ी : ऑडिट में पैसे को इधर से उधर किए जाने के अलावा संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन के साथ-साथ कुछ अन्य तरह की गड़बड़ियां भी पकड़ी गई हैं, जिनमें बैंकों का सहारा भी लिया गया। फॉरेंसिक ऑडिट के तहत धोखाधड़ी और वित्तीय गड़बड़ियों के आंकड़े और साक्ष्य जुटाने के मकसद से किसी संस्था या कंपनी के खातों और लेनदेन की जांच किसी स्वतंत्र आकलन किया जाता है। इसने जेपी इन्फ्राटेक जैसे मामलों में इस बात से पर्दा उठाया है कि इसकी पैरंट कंपनी जयप्रकाश असोसिएट्स ने बैंकों से लोन लेने के लिए जेपी इन्फ्राटेक के पास पड़ी जमीन का किस तरीके से इस्तेमाल किया। इसी तरह, ऐमटेक ऑटो और भूषण स्टील के मामलों में गड़बड़ियां सामने आई हैं। दो साल में 1,484 कंपनियों पर लगाम

आईबीसी के तहत लाए गए ज्यादातर मामलों में नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा नियुक्त रेजॉलुशन प्रफेशनल्स फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं। कुछ मामलों में कर्जदाताओं ने इन्सॉल्वंसी प्रोसेस के लिए कंपनियों को एनसीएलटी में भेजे जाने से पहले उनकी फॉरेंसिक ऑडिट की थी। गौरतलब है कि दिसंबर 2016 में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वंसी रेजॉलुशन का प्रावधान लागू होने के बाद से दिसंबर 2018 तक 1,484 मामले आईबीसी के तहत कार्रवाई के लिए लाए जा चुके हैं। इनमें 900 मामलों को निपटाना बाकी है। कुल मामलों में आधे वेंडरों जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटरों ने कंपनियों को आईबीसी में घसीटे हैं।

रिलायंस की ई-कॉमर्स बाजार में एंट्री से ऑनलाइन रिटेल बिजनेस बड़ा होगा : फ्लिपकार्ट सीईओ

मुंबई, 23 अप्रैल (ए)। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भी कदम रखने जा रही है। कंपनी का कहना है कि जैसे जीयों ने मार्किट में धमाकेदार एंट्री के साथ दूरसंचार क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। वैसे ही रिलायंस देश के ई-कॉमर्स क्षेत्र में बड़े उलटफेर कर देगा। इस क्षेत्र की दिग्गज फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को टक्कर देगा। हालांकि, फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति की इस बारे में सोच कुछ अलग है।

नए नवाचारों को होगें बड़े फायदें: केंद्र सरकार द्वारा फरवरी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए नियमों को सख्त करने के बाद भारत में ऑनलाइन रिटेल की पहुंच बहुत कम हो गई है। इसका आकार फैलाने के लिए इसकी राह में आने वाली कुछ दिक्कतों को दूर करने की जरूरत होगी। एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में कृष्णमूर्ति का कहना है कि हमारा मानना है कि अगर इस क्षेत्र में ज्यादा खिलाड़ी होंगे तो इससे बाजार और बड़ा होगा। यह सभी हितधारकों जैसे किराना स्टोर्स, छोटे और मध्यम आकार के मर्चेंट्स और उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा। इन सभी हितधारकों को क्षेत्र में नित ।

अमेजॉन और फ्लिपकार्ट देगा टक्कर: दुनिया के 13वें सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी इस साल के अंत में अपनी ऑनलाइन रिटेल कंपनी लॉन्च कर ऑनलाइन रिटेल मार्केट में खलबली मचा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस ग्रुप ने अपने ब्रांड को फ्लिपकार्ट और अमेजॉन सहित अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों के ऑनलाइन मार्केटप्लेस से हटाना शुरू कर दिया है। मॉर्गन स्टेनली के अनुमान भारतीय ई-कॉमर्स बाजार में जेफ बेजॉस की अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दो दिग्गज कंपनियां कारोबार कर रही हैं।

मार्किट में बढ़ेगा निवेंश: वर्ष 2027 तक इनका कारोबार 200 अरब डॉलर को छू सकता है। तेल से लेकर रिटेल तक का कारोबार करने वाली कंपनी के लिए रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल के जरिये ई-कॉमर्स का फायदा उठाने का माकूल मौका है। कृष्णमूर्ति ने कहा है कि फ्लिकार्ट उन सभी कायदे-कानून का समर्थन करती है। जिससे क्षेत्र में स्थिरता लाने और एक ग्रोथ आधारित नियामकीय ढांचा बनाने में मदद मिलती है। मर्चेंट और ग्राहक दोनों को फायदा होता है। उन्होंने कहा है कि एक फरवरी के बाद ई-कॉमर्स के नियमों में बदलाव होने के बाद फ्लिपकार्ट के कारोबार पर से कोई फर्क नहीं पड़ा है।

दूरसंचार विभाग ने तैयार किया कैबिनेट नोट का मसौदा, 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी बीएसएनएल और एमटीएनएल

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (ए)। नकदी संकट में जूझ रही दूरसंचार विभाग की सरकारी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित करने मसौदा भेजा गया है। दोनों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने के बारे में परामर्श के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा कई मंत्रालयों को भेजा है। एक अधिकारी ने कहा है कि विभाग ने इन प्रस्तावों पर विभिन्न मंत्रालय से उनकी टिप्पणियां मांगी हैं। इस पर कुछ प्रमुख मंत्रालयों से टिप्पणियां मिलने का इंतजार है। दूरसंचार कंपनियों में बीएसएनएल पर सबसे कम 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी ने पूरे देश के लिए सरकार से 7,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश के माध्यम से 4जी स्पेक्ट्रम मांगा है। कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम की लागत 14,000 करोड़ रुपये पड़ेगी। दोनों सरकारी कंपनियों पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन का बोझ ज्यादा है क्योंकि इनके गठन के समय बड़ी संख्या में दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को इनमें भेजा गया था। देशभर में बीएसएनएल के कर्मचारियों की संख्या 1.76 लाख और एमटीएनएल की 22,000 है। दोनों कंपनियों ने गुजरात मॉडल के आधार पर अपने कर्मचारियों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कहा है। गुजरात मॉडल के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को उसकी अब तक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के हिसाब से हर साल के 35 दिन और बची हुई सेवा के सालों के लिए हर साल के 25 दिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है।

डीओटी ने दी टाटा के विलय को मंजूरी, एयरटेल को देनी होगी 7200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (ए)। दूरसंचार विभाग ने भारती एयरटेल में टाटा टेलीसर्विसेज के विलय को मंजूरी दे दी है लेकिन इसके लिए एयरटेल से 7,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी मांगी है। डीओटी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 9 अप्रैल को विलय को सर्शत मंजूरी दी थी। टाटा टेली पर सरकार का कुछ बकाया है। इसे भी पहले चुकाना पड़ेगा। एयरटेल ने अक्टूबर 2017 में टाटा टेलीसर्विसेज को खरीदने की घोषणा की थी। दोनों कंपनियों के बोर्ड और रेगुलेटर्स की मंजूरी के बाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसी साल जनवरी में विलय के प्रस्ताव को मंजूर किया था। इसके बाद सिर्फ डॉट की स्वीकृति बाकी रह गई थी। डील की शर्तों के मुताबिक एयरटेल 19 टेलीकॉम सर्किल में टाटा के मोबाइल बिजनेस का अधिग्रहण करेगी। मोबाइल बिजनेस में इसकी दो कंपनियां हैं। टाटा टेलीसर्विसेज और टाटा टेली महाराष्ट्र। टाटा टेलीसर्विसेज का ऑपरेशन 17 सर्किल में और टाटा टेली महाराष्ट्र का 2 सर्किल में है। टाटा को स्पेक्ट्रम के भी कुछ पैसे देने हैं। एयरटेल इसे चुकाने पर सहमत है। इस डील से 1800, 2100 और 850 मेगाहर्ट्ज बैंड में एयरटेल को कुल 178.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। इस स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल 4जी में होता है। टाटा टेली के सभी ग्राहक एयरटेल के ग्राहक बन जाएंगे।

ग्रेटर नोएडा में महज एक रुपए में फ्लैट बेच दिए

ग्रेटर नोएडा, 23 अप्रैल (ए)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विभिन्न आरोपों को झेल रही रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली के बारे में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। आम्रपाली ने मात्र एक रुपए में भी फ्लैट बेचे हैं। कुछ लोगों को फ्री में फ्लैट दिए गए। आम्रपाली जैसी स्थिति से बचने के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अब नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत आवंटित प्लॉट के अविकसित हिस्से का आवंटन रद्द करने और सरेंडर करने का नियम बनाने की योजना बनाई जा रही है। इस तरह पार्ट कैंसिलेशन से परियोजना में फंसे बायर्स और अथॉरिटी दोनों को फायदा हो सकेगा।

42 हजार होम बायर्स परेशान: ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का आम्रपाली पर करीब 3 हजार करोड़ रुपए बकाया है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली के करीब 42 हजार बायर्स घर की आस में भटक रहे हैं। केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अथॉरिटी ने अपनी तरफ से 48 बिल्डरों की परियोजनाओं का ऑडिट कराया था। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आम्रपाली ने कुछ लोगों को मात्र एक रुपए में भी फ्लैट बेचे थे। कई लोगों को फ्री में भी फ्लैट दिए गए। इनमें कई प्रभावशाली लोग बताए गए हैं।

104 बिल्डरों पर लगभग 6 हजार करोड़ बकाया: ग्रेनो अथॉरिटी पर आम्रपाली समेत 104 बिल्डरों पर 6 हजार करोड़ रुपए बकाया है। काफी ऐसे बिल्डर हैं, जिन्होंने आवंटित जमीन के कुछ हिस्से पर ही निर्माण और बुकिंग की है। ऐसे हिस्से को वापस लेकर अथॉरिटी बकाया वसूल सकती है, लेकिन इसका नियम अभी नहीं है। साथ ही अगर उस हिस्से में भी बिल्डर ने हवा में ही बुकिंग कर ली हो तो ऐसे बायर्स को भी अथॉरिटी जमीन वापस लेने के बाद रिफंड कर सकेगी।

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऑटोमोबाइल मार्केट बना भारत

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (ए)। पिछले वर्ष वीकल्स बनाने की संख्या के लिहाज से दुनिया में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऑटोमोबाइल मार्केट रहा। फ्यूल प्राइसेज, इंटरेस्ट रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ने से देश में वीकल्स की डिमांड पर असर पड़ा। इसके बावजूद ऑटोमोबाइल प्रॉडक्शन में वृद्धि हुई। साल 2018 में ग्लोबल ऑटोमोबाइल प्रॉडक्शन एक दशक में पहली बार 1.1 पर्सेंट गिरकर 9,56,34,593 यूनिट रहा। इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के डेटा के अनुसार, भारत में ऑटोमोबाइल प्रॉडक्शन (पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स) टॉप 10 देशों में सबसे अधिक बढ़ा। यह पिछले वर्ष 8 पर्सेंट की वृद्धि के साथ लगभग 51.7 लाख यूनिट रहा। दूसरे स्थान पर 5.2 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ 28.7 लाख यूनिट बनाकर ब्राजील रहा। चीन में ऑटोमोबाइल प्रॉडक्शन 4.2 पर्सेंट गिरकर 2.78 करोड़ यूनिट का था। अमेरिका और जापान में यह क्रमशः 1.1 पर्सेंट और 0.4 पर्सेंट बढ़ा।

भारत में पैसेंजर वीकल्स का प्रॉडक्शन 2.8 पर्सेंट बढ़कर 40,64,774 यूनिट और कमर्शियल वीकल्स का 34 पर्सेंट की वृद्धि के साथ 11,09,871 यूनिट का था। एवेंटम पार्टनर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर वी जी रामाकृष्णन ने बताया, प्रॉडक्शन में इस ग्रोथ के पीछे विशेषतौर पर कमर्शियल वीकल्स की सेल्स में बढ़ोतरी का कारण है। भारत एकमात्र बड़ा देश में जहां ग्रोथ अच्छी है। अगर वैश्विक मंदी से एक्सपोर्ट पर असर न पड़ता तो देश में प्रॉडक्शन और बढ़ सकता था। फ्यूल की कीमतों, इंश्योरेंस कॉस्ट के महंगा होने और वर्ष की दूसरी छमाही में ड्डरूस्नस्र संकट के बाद मार्केट में लिक्विडिटी घटने के कारण डिमांड पर असर पड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री के जानकारों को मौजूदा फाइनैंशल इयर में ग्रोथ तेज होने की उम्मीद है। देश की सबसे बड़ी कार मेकर मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने हाल ही में ईटी को बताया था, अगले कुछ महीनों में सेफ्टी और एमिशन से संबंधित कुछ रेगुलेशन लागू होंगे। इससे कीमतें बढ़ सकती हैं और कस्टमर्स इससे पहले वीकल खरीदना पसंद कर सकते हैं। देश में ऑटोमोबाइल सेल्स अगले फाइनैंश इयर में गिरने की

आशंका है, लेकिन इसके लिए लंबी अवधि की संभावनाएं अच्छी हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर (सेल्स एंड मार्केटिंग) एन राजा ने कहा, विकसित देशों में लोग पुराने वीकल बदलने के लिए नई कारें खरीदते हैं। लेकिन भारत में नई कारों की बिक्री का बड़ा हिस्सा पहली बार कार खरीदने वालों से आता है। देश में नई कार की बिक्री में पहली बार कार खरीदने वालों की हिस्सेदारी 35-40 पर्सेंट की है। देश में लंबी अवधि में ऑटोमोबाइल सेल्स बढ़ने की मजबूत संभावना है।

मारुति आल्टो 2018-19 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार: मारुति सुजुकी इंडिया की एंट्री लेवल हैचबैक आल्टो साल 2018-19 में सबसे ज्यादा बिकने वाली पैसेंजर व्हीकल रही। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के मुताबिक, टॉप 10 मॉडल्स में से सात मारुति की रहीं। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की तीन गाड़ियां भी ज्यादा बिक्री वाली टॉप 10 पैसेंजर वीकल्स में शामिल रहीं। आल्टो की 259401 गाड़ियां 2018-19 में बिकीं। इस तरह उसने पहले स्थान पर कब्जा बरकरार रखा। इससे पिछले वित्त वर्ष में उसकी 2,58,539 कारें बिकी थीं।

मारुति की कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर 2,53,859 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। कंपनी की प्रीमियम हैचबैक ने 2,23,924 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं बलेनो 2,12,330 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रही। एसयूवी विटारा ब्रेजा 1,57,880 यूनिट्स की बिक्री के साथ वित्त वर्ष 2017-18 के मुकाबले दो पायदान चढ़कर पांचवें स्थान पर पहुंच गई। एचएमआईएल की एलीट आई20 की 1,40,225 यूनिट्स बिकीं और यह छठे स्थान पर रही।